खिलौना उद्योग के लिए सरकार की कैपिटल इंसेंटिव स्कीम तैयार

क्लस्टर निर्माण, कौशल विकास और ब्रांडिंग के लिए इंसेंटिव देगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारतीय खिलौना उद्योग को दुनियाभर के बाजार में पहचान दिलाने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत सरकार खिलौना मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, श्रमिकों के कौशल विकास और भारतीय खिलौने की ब्रांडिंग व उसके प्रोत्साहन के लिए इंसेंटिव देगी। दुनिया की शीर्ष 50 खिलौना कंपनियों को भारत में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने या भारतीय खिलौने को खरीदने के लिए तैयार किया जा रहा है।

बुधवार को इस पूरी योजना को साझा करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में 15 मंत्रालयों और नौ राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा उद्योग जगत के 120 साझेदारों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय खिलौना उद्योग के विकास व उसकी ब्रांडिंग की सार्वजनिक रूप से इच्छा जाहिर कर चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक खिलौना उद्योग के प्रोत्साहन के लिए इंडियन फुटवियर, लेदर एंड एसेसरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम की तर्ज पर इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत क्लस्टर डेवलपमेंट, कौशल विकास और उत्पाद के ब्रांडिंग के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इंसेंटिव कम से कम तीन वर्षों तक दिए जा सकते हैं।

डीपीआइआइटी के मुताबिक खिलौना उद्योग के समग्र विकास के लिए खिलौना के कंपोनेंट इकोसिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है। उद्योग विभाग अपने स्तर पर फर्नीचर, टूलिंग, प्लास्टिक, मोल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स व टेक्सटाइल से जुड़ी उन कंपनियों की पहचान में जुटा है जो खिलने या उसके पुर्जे बना सकती हैं। खिलौना उद्योग मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग 13 देशों के साथ वेबिनार का आयोजन कर चुका है। वहीं घरेलू स्तर पर कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के साथ कई चरण की बातचीत एवं वर्कशॉप का आयोजन किया जा चुका है।

भारतीय खिलौना बाजार में 85 फीसद हिस्सेदारी आयातित खिलौनों की है, जिसका 90 प्रतिशत तक हिस्सा चीन से आयात हो रहा है। वर्ष 2019 में भारत का खिलौना कारोबार लगभग 13,125 करोड़ रुपये का रहा। विश्व का खिलौना बाजार 90 अरब डॉलर यानी 6.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है।